हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 13 फ़रवरी 2026, समय 1305 (5 मिनट)

आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है- रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। यह थीम प्रसारण व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिवस रेडियो से जुड़े लोगों के प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दूर-दराज के गांवों से लेकर व्यस्त शहरों तक लोगों को एक विश्वसनीय आवाज के रूप में सेवाएं देता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वर्षों से रेडियो ने समय पर सूचनाएं पहुंचाने, प्रतिभाओं को मंच देने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। अपने कार्यक्रम 'मन की बात' का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने समाज की शक्ति को उजागर करने में रेडियो क्षमता का अनुभव किया है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश के किसानों की चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी कभी भी

किसानों के सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं रहे हैं और अकसर राष्ट्रविरोधी बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी झूठ फैलाकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे है। उनका हर निर्णये किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिन्दगी बदल दी है और अभी अमरीका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित है

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का आशा और विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 11 वर्ष के शासनकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री कल सूरजकुंड मेला के दौरान राजहंस पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व में नई पहचान बनी है। आज पूरी दूनिया भारत को आशा भरी नजरों से देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरा विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। विपक्ष बौखलाहट में अनापशनाप बयानबाजी करना इसका प्रमाण है। सूरजकुंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर हस्तशिल्प मेले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविख्यात इस मेले में अब तक 10 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं।

मेले में देश-विदेश के प्रसिद्ध कारीगर अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह मेला कला का एक अनूठा संगम है।

हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता,

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह बढ़ी हुई दरें 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगी, जिनका भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। सरकारी आदेशों के अनुसार लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बौने व्यक्तियों सहित दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज-III एवं स्टेज-IV के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता तथा किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। एसिड पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया गया है। अब दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर 3200 रुपये को आधार मानते हुए सहायता दी जाएगी। 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 8000 रुपये, 50 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 11200 रुपये, तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 14400 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार स्कूल न जाने वाले विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को वित्तीय सहायता बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि 2400 रुपये से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में भी ब�ोतरी की गई है। इसके तहत एक बच्चे पर 2300 रुपये प्रतिमाह तथा दो बच्चों पर 4600 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा राज्य में बसे कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब एक व्यक्ति को 1700 रुपये प्रतिमाह, जबकि एक परिवार को अधिकतम 8500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।